Ridge Management Supervisory Committee under the Chairmanship of Secretary, Environment and Forests/ Inspector General of Forests, Ministry of Environment and Forests, Government of India and Secretary (Forests), Government of National Capital Territory of Delhi as the Member Secretary.

प्रदूषण को रोकने के लिए उठाए गए कदम

7665. **श्री रामजी लाल:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बावजूद प्रदूषण बढ़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रयोजन हेतु राज्यों को अपेक्षित सहायता देगी; यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान यदि कोई सहायता दी गई है, तो उसका राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने इस प्रयोजन के लिए इस वर्ष के बजट में कितना आबंटन किया है;

(घ) इसके परिणामस्वरूप वन क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई है;

(ङ) मंत्रालय किसानों के सक्रिय सहयोग से कौन-कौन सी योजनाएं चला रहा है; और

(च) इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप हरियाणा के किसानों को जो लाभ मिला है, उसका ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री कमल नाथ): (क) जी, हां। कुछ पैरामीटरों के मामलों में कतिपय क्षेत्रों में प्रदूषण में वृद्धि हुई है।

(ख) वर्ष 1991-92, 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान "प्रदूषण के उपशमन के लिए सहायता" नामक स्कीम के अंतर्गत राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/राज्य परिवहन विभागों/संघ राज्य क्षेत्रों को दी गई वित्तीय सहायता को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है:—

क्र०सं०	राज्य बोर्ड का नाम	वर्ष जिनके दौरान वित्तीय सहायता दी गई (रुपयों में)		
		1991-92	1992-93	1993-94
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	—	—	—
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—
3.	असम	—	—	10,00,000
4.	बिहार	—	12,25,000	—
5.	गुजरात	—	8,07,981	6,83,722
6.	हरियाणा	12,00,000	8,58,000	—
7.	जम्मू और कश्मीर	—	—	—
8.	हिमाचल प्रदेश	—	—	—
9.	कर्नाटक	15,00,000	21,23,428	4,20,000
10.	केरल	4,00,000	6,75,000	18,54,288
11.	मध्य प्रदेश	5,80,000	8,00,000	—
12.	महाराष्ट्र	—	—	—
13.	मणिपुर	—	—	—
14.	मिज़ोरम	—	—	2,40,000
15.	मेघालय	—	—	22,26,805
16.	नागालैण्ड	—	—	—
17.	उड़ीसा	—	—	—
18.	पंजाब	10,65,000	1,80,000	—
19.	राजस्थान	7,09,000	7,75,000	—
20.	सिक्किम	—	—	2,00,944

1	2	3	4	5
21.	तमिलनाडु	—	15,00,000	—
22.	त्रिपुरा	—	6,71,700	—
23.	उत्तर प्रदेश	22,14,000	15,00,000	7,75,368
24.	पश्चिम बंगाल	—	—	—
	कुल:	76,68,000	1,11,16,109	74,01,127

क्र०सं०	राज्य सरकार के विभागों के नाम	वर्ष जिनके दौरान सहायता दी गई		
		1991-92	1992-93	1993-94
	पर्यावरण विभाग:			
1.	कर्नाटक	—	7,88,445	—
2.	पंजाब	5,10,000	5,00,000	—
3.	तमिलनाडु	5,84,000	—	—
4.	पश्चिम बंगाल	5,00,000	1,69,626	—
	राज्य विभाग— कुल:	15,94,000	14,58,071	—
संघ राज्य क्षेत्र:				
1.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	—	3,66,000	3,65,120
2.	चण्डीगढ़	7,04,000	4,63,419	9,77,047
3.	दमन, दीव, दादरा और नगर हवेली	—	7,15,700	—
4.	दिल्ली	6,05,000	12,71,700	9,50,000
5.	पाण्डिचेरी	—	3,17,500	—
	संघ राज्य क्षेत्र—कुल:	13,09,000	31,33,819	22,92,167

(ग) वित्तीय वर्ष 1994-95 के दौरान प्रदूषण के उपशमन के लिए सहायता हेतु 2 करोड़ रुपये आबंटित किये गये हैं।

(घ) भारतीय वन सर्वेक्षण की 1993 की वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र में 925 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। वन संरक्षण के लिए आवंटित निधियां "प्रदूषण के उपशमन के लिए सहायता" स्कीम से भिन्न है।

(ङ) यह मंत्रालय "अवक्रमित क्षेत्रों की बहाली में अनुसूचित जनजातियों और निर्धन ग्रामीणों को शामिल करना" नामक स्कीम के अंतर्गत राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता देता है।

(च) इस स्कीम के अंतर्गत हरियाणा को कोई सहायता नहीं दी जाती है क्योंकि यहां अनुसूचित जनजाति की आबादी अपेक्षाकृत कम है।

Illegal Felling of Trees in Jammu and Kashmir

7666. SHRI JAGMOHAN: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that during the last three years, forests have been cut illegally on a large scale in the State of Jammu and Kashmir by the militants and their collaborators and whether this has exposed vast areas of the State to the risk of ecological degradation, including soil erosion, beside depleting its forest wealth and resources; and

(b) what remedial action if any, has been taken by Government in this regard?